कामकाजी महिला

वर्ष 3 अंक 1 अक्टूबर, 1990 मूल्य : 2 रु०

सरकार त्रिपुरा में अविलंब कार्रवाई करे

विमल रणदिवे

पिछली 8 जुलाई को त्रिपुरा में हुए जिला परिषद के चुनावों में अमानवीय आतंक के नंगे नाच की रिपोर्टों से मजबूर होकर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने श्री यशवंत सिन्हा सांसद के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय दल त्रिपुरा में तफ्तीश करने के लिए भेजा। दल ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को त्रिपुरा के विभिन्न हलकों में 5000 लोगों से मुलाकात की, 701 व्यक्तिगत शिकायतें प्राप्त कीं और विभिन्न संगठनों के 34 प्रतिनिधिमंडलों से मिला। पुरुष व महिलाओं ने सी. पी. आई. (एम) का समर्थन देने वाले आम लोगों और जनजातियों पर इंका—टी. यू. जे. एस. गठबंधन द्वारा बरपाए गए कहर की दास्तान सुनाई। 50 अन्य महिलाओं के साथ आईं श्रीमति गीता देवनाथ (महिला संगठन) ने ज्ञापन देते हुए दल को बताया कि किस तरह उन्हें बूथ से खदेड़ा गया और वोट नहीं देने दिया गया। पूरा क्षेत्र ही इंका-टी. यू. जे. एस. गठबंधन के मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा मंगाए गए बाहरी गिरोहों द्वारा कब्जे में किया गया था। दल ने पाया कि छोटी लड़कियों, जनजातीय व गैर-जनजातीय नारियों के साथ बलात्कार के असंख्य हादसे हुए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद एक भी अभियुक्त पकड़ा नहीं गया। महिलाओं को इन छुट्टा अपराधियों के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं दी गई।

यहां एक गौरतलब बात यह है कि बलात्कार को आम लोगों के खिलाफ एक वर्ग-हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है—युवा जनजातियों एवं उनके परिवारों को सी. पी. आई. (एम) को समर्थन देने की वजह से धमकी दी जा रही है कि यदि उन्होंने सत्ता का कहना नहीं माना तो उनका यही हश्र होगा। उजान मैदान खोवाई में 31 मई और जून के प्रथम सप्ताह (1988) में हुए व्यक्तिगत और गिरोह बलात्कारों की तमाम जनवादी ताकतों ने निंदा की थी। 12 वर्षीया पंचलक्ष्मी

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

सरकार त्रिपुरा में अविलंब कार्रवाई करे	2
कर्नाटक राज्य की रिपोर्ट	3
केरल में कामकाजी महिलाओं का सफल अधिवेशन	4
एक बार फिर 7 अगस्त की रैली में आने के लिए वेतन कटा	7
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की कानपुर बैठक के फैसले	8
तमिलनाडु कामकाजी महिला समन्वय समिति की रिपोर्ट	12
महिलाओं पर अत्याचारों की केंद्र सरकार न्यायिक जांच कराये	16
कोलियरी अस्पताल की नर्सों ने धनबाद में अधिवेशन आयोजित किया	17
सामंती व्यवहारों का विचित्र उदाहरण	18
नागल बाल विकास परियोजना की आंगनवाड़ी सहायिका की कुछ माँगें	19
बिहार राज्य ज० म० स० डॉ० अम्बेडकर जन्म शताब्दी मनाया	19
महिलाओं के लिए सामूहिक बार्गेनिंग की प्रोन्नति के लिए सम्मेलन	20
विमान परिचारिका लीना ठक्कर की मृत्यु पर ए. सी.ई.यू. और ए.आई.एच.ए. का संयुक्त वक्तव्य	22

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

कर्नाटक राज्य की रिपोर्ट

एम. एम. राजम्मा, कर्नाटक

कर्नाटक सीटू में तकरीबन 30 प्रतिशत महिलाएं हैं, पर वे असंगठित क्षेत्रों में हैं । इसलिए उन्हें कमेटी बैठकों या ट्रेड यूनियन कार्यों में हिस्सा लेने के लिए लामबंद करने में हमें काफी मुश्किलें पेश आती हैं ।

कर्नाटक के बीड़ी मजदूर (जिनमें से 90% महिलाएं हैं) कई समस्याओं से जूझ रहे है । दो दिन का काम और चार दिनों की भूखमरी आम बात है । तेंदु पत्तों की कमी की वजह से यह संकट है । वस्तुत: कोई कमी नहीं है और यह कमी जनता दल सरकार के पतन के बाद आई इंका सरकार ने पैदा की है । इन महिलाओं को नतीजतन निजी पार्टियों के पास जाना पड़ता है, जो चार दिन के कार्यों के लिए कम मजदूरी देते हैं । हलांकि सीटू ने मामले को गंभीरतापूर्वक उठाया है, महिला मजदूरों की चेतना जागृत करने के प्रयास किये जाने चाहिएं ।

एक अन्य समस्या कॉफी उत्पादक उद्योगों की है । कर्नाटक देश की 80% कॉफी उपजाता है और मशीनीकरण की वजह से महिलाओं को काम से निकाला जा रहा है । इसके अलावा इस साल फसल उगा दी गई है ।

नव-निर्वाचित सदस्यों की हमारी पहली कमेटी मीटिंग 1 जुलाई को हुई । 22 निर्वाचितों में से मात्र 12 ने बैठक में भाग लिया । विभिन्न जिलों की रिर्पोटों के बाद बैठक में निम्नांकित मुद्दों पर चर्चा हुई ।

तय किया गया कि जिला और क्षेत्र स्तर पर समितियां बनाई जाएं । स्थानीय समितियों के गठन के लिए सीटू का परामर्श लिया जाना चाहिए । सभी कामरेडों ने कमेटी संगठित करने और राज्य को सूचित करने की सहमति दी । जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनवाने और कार्यावधि में यातायात सुविधा के लिये दबाव डालने का निर्णय लिया गया ।

डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. सी. ने 7 अगस्त को दिल्ली में आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं की रैली के आह्वान को समर्थन देने का निर्णय लिया । दिल्ली की रैली के लिए कम से कम 10 सदस्य भेजे जायंगे ।

ट्रेड यूनियन (सीटू) में कामकाजी महिलाओं की स्थिति निम्नवत है—

सीटू के हुबली के 5 वें सम्मेलन (मार्च 1989) में—

कुल सदस्यता	47772	महिलाएं 18098	38%
प्रतिनिधि संख्या	266	37	
पर्यवेक्षक	17	3	14%
राज्य परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या	15	कुल 130	
राज्य कमेटी	5	36	

1. बीड़ी फेडरेशन (राज्य 3, महिला पदाधिकारी कमेटी में 33 में से 8.

कुल सदस्यता 23000, महिलाएं 90% (कुल बीड़ी मजदूर 3 लाख)

2. कर्नाटक होट्टा कर्मिकार संघ सकेलशपुर 50% महिलाएं—चंद्रकला—सहायक सचिव, (बनजा, कुप्पु, चेल्लम्मा—एक्जेक्यूटिव कमेटी सदस्य).

कॉफी प्लांटेशन के राज्य संगठन की बैठक में उन्हें पदाधिकारी चुना गया ।

सीटू राज्य कमेटी हम महिलाओं को ट्रेड यूनियन मामलों में आगे आने में मदद कर रही है ।

हमारे राज्य में बैंक एवं जीवन बीमा महिलाएं अलग से संगठित हैं और डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. सी. उनसे संपर्क नहीं साध सकी, लेकिन हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षिकाओं से संबंध स्थापित कर पाईं । हमें संतोष है कि हमारी कामकाजी महिलाएं राज्य सीटू के आह्वानों में शिरकत कर रही हैं । इंका सरकार द्वारा हाल के बस भाड़ों में वृद्धि पर आयोजित पिकेटिंग कार्यक्रम में हमारी कई कार्यकर्ताएं गिरफ्तार हुई और अन्य सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रहीं ।

केरल में कामकाजी महिलाओं का सफल अधिवेशन

ए. नजीमुन्नीसा, केरल

केरल राज्य कामकाजी महिला अधिवेशन 14-15 जुलाई, 1990 को कोजीकोड में आयोजित किया गया।

राज्य समन्वय समिति ने 3.5.90 को बैठक में अधिवेशन करने का फैसला लिया। सीटू राज्य कमेटी के महासचिव का. के. एन. रवीन्द्रनाथ और का. सुशीला गोपालन के निर्देशन में कमेटी ने तय किया कि जिलों में मजदूर सभाएं की जाएं और कमेटी के पदाधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन कर उन पर रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया ताकि बहस के मुद्दे तैयार हों। सीटू राज्य कमेटी और ट्रेड यूनियन नेताओं की उप-समिति ने सीटू जिला कमेटियों और सेवा संगठनों को दिए जानेवाले निर्देशनों के ब्यौरे पर भी बातचीत की। तदनुसार जिला कमेटी एवं यूनियनों ने विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि भेजने की योजना तैयार की। सीटू, समन्वय समिति यूनियन और संगठनों के इस सम्पूर्ण प्रयास से हम अधिवेशन को सफल तौर पर आयोजित कर सके।

कामकाजी महिलाओं की जिला समिति को अधिवेशन के पहले पुनर्गठित किया गया और कोजीकोड में एक स्वागत समिति बनाई गई। इससे तीसरे राज्य अधिवेशन को आयोजित करने में काफी मदद मिली।

प्रतिनिधियों के पंजीकरण के बाद, स्वागत समिति के अध्यक्ष का० एम. वसु ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

तब का० बी. टी. आर. जिन्होंने सीटू में महिलाओं को संगठित करने की पहल की थी, को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों ट्रेड यूनियन एवं महिला नेताओं जिन्होंने हमारा साथ पिछले वर्षों में छोड़ दिया को भी श्रद्धांजलियां दी गई।

सम्मेलन का उद्घाटन विधायक प्रो० जबीसा उम्मल ने किया। निरक्षरता, बेकारी आदि समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने कामकाजी महिलाओं से आह्वान किया कि देश के उत्थान के लिए जनवादी आंदोलनों में वे शिरकत करें, साथ ही अपनी मांगों की उपलब्धि की लड़ाई लड़ते रहें। चूंकि केरल की 60% निरक्षर महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के शिक्षित तबकों को सरकार की निरक्षरता दूर करने के कार्यक्रमों में हाथ बंटाना चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में का० के. आर. भानुमती ने कहा कि समन्वय समिति असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को लामबंद करने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं।

सीटू राज्य कमेटी के महासचिव, का० के. एन. रवीन्द्रनाथ ने सभा को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दशाओं का विस्तृत ब्यौरा देते हुए उन्होंने दिखाया कि वे किस तरह मजदूरों की जिन्दगी, उनके संघर्षों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि शांति आंदोलन को मजबूत बनाने के सोवियत संघ के निरंतर प्रयासों की हम सराहना करते हैं। हलांकि महाशक्तियों के बीच संधि है फिर भी अमरीका अभी भी तृतीय विश्व के देशों में हस्तक्षेप करने उन पर आक्रमण करने का अधिकार सुरक्षित रखे हुए हैं। पनामा, अफगानिस्तान, अरब-इस्राइल आदि के मुद्दे इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। वह पाकिस्तान को भी सारी सहायता देने पर आमादा है, जो भारत की सार्वभौमिकता को नष्ट करने के मौके में रहता है। यदि हम अमरीका के शांति आंदोलन को समाप्त करने के प्रयासों के बारे में सचेत नहीं है तो शांति आंदोलन को मजबूत बनाने की लड़ाई नहीं कर सकते। समाजवादी देशों के हाल के विकासक्रम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हमें समाजवाद विरोधी अभियानों का प्रतिवाद करना है चूंकि समाजवाद ही शोषण एवं अन्य सामाजिक बुराइयों से लड़ने का एकमात्र तरीका है।

उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर वर्ग ने इंका शासन की समाप्ति में एक अहम भूमिका निभाई। हलांकि मजदूरों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों की ओर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का रवैया आशाजनक है, पुरानी आर्थिक नीतियों को बदलने का कोई गंभीर प्रयास नहीं दीखता।

सांप्रदायिक दंगों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बल दिया कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को धर्मनिरपेक्षता की भावना से सुदृढ़ करना होगा और हमें सांप्रदायिकता से लड़ना ही है; उन्होंने दुहराया कि कामकाजी महिलाओं को सांप्रदायिकता के खिलाफ अभियानों में

शिरकत करनी चाहिए।

अपने भाषण का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि समन्वय समिति सीटू एवं इसके सहानुभूतिकर्त्ताओं का मंच है; यह कामकाजी महिलाओं का मंच भी बने ताकि इससे ट्रेड यूनियन आंदोलन मात्र मजबूत हो सके।

कार्य की रिपोर्ट

का० नजीमुन्नीजा द्वारा पेश रिपोर्ट में कामकाजी महिलाओं के विशेष सत्र, ट्रेड यूनियन आंदोलन और आम संघर्षों में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी, एड्वा के साथ संयुक्त कार्रवाइयों और विभिन्न संगठनों की महिला कमेटियों और उनकी मांगों पर अलग अभियानों आदि की चर्चा हुई। प्लांटेशन, काजू, क्वायर, मत्स्य, आंगनवाड़ी, निजी अस्पतालों, कृषि फार्म, शिक्षकों, केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों आदि की विभिन्न समस्याओं, संघर्षों पर भी बात हुई। 'व्वायस ऑफ वर्किंग वीमेन' और तुलचाथा (एड्वा की केरल राज्य कमेटी का मुखपत्र) के वितरण/पाठकतत्व पर भी चर्चा हुई।

दो घंटे के लिए समूह-बहस के अवकाश के बाद हर जिले से एक प्रतिनिधि ने रिपोर्ट पर अपना मत रखा। राज्य एवं जिला समन्वय समितियों की कार्यविधि पर उन्होंने कहा कि जहां मध्यवर्गीय यूनियन और कर्मचारी महिलाओं की समस्याओं को उठाने के ज्यादा इच्छुक हैं, सीटू यूनियन उतना ध्यान नहीं देते। चूंकि सीटू के तहत ज्यादा महिलाएं संगठित हैं अतः कमेटी बैठकों में उनकी शिरकत अनिवार्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंगनवाड़ी मजदूरों एवं दुकानों एवं निजी अस्पतालों के मजदूरों को संगठित करने के लिए उन्होंने सीटू से और अधिक मदद चाही।

अधिकांश जिलों में उन्होंने कहा कि एड्वा के साथ 8 मार्च को मूल्य वृद्धि, बेकारी आदि पर संयुक्त कार्रवाइयां की गई। का० रवीन्द्रनाथ द्वारा उठाए गए बिंदुओं की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि उन्हें और राजनीतिक शिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह सब जोड़ा जाए कि महिला कार्यकर्ताओं के लिए टी. यू. क्लास होने चाहिएं। उन्होंने मलयालम में 'व्वायस ऑफ वर्किंग वीमेन' की मांग की और 'तुलयाथा' का प्रकाशन जारी रखने का निवेदन किया, जो उनके लिए काफी मददगार है। साथियों ने फंड के अभाव में कार्य करने की दिक्कतों की भी चर्चा की।

रिपोर्ट पर बहस

विभिन्न यूनियनों का प्रतिनिधित्व करनेवाले साथियों ने रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लिया। श्री चित्रा मेडिकल सेंटर की का० नारायणी ने कहा कि यूनियन के हस्तक्षेप की बदौलत वे अपनी कार्यावधि 8 घंटे पर तय कर पाई। का० नारायणी ने शिकायत की कि यूनियन भारवाहक मजदूरों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा। आंगनवाड़ी की का० वल्लीकुट्टी ने सभी यूनियनों के सहयोग और सीटू से संघर्ष जारी रखने की अपील की। खादी मजदूर का० गीता ने कहा कि खादी आयोग उन्हें मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि गांधी जयंती की छुट्टी नहीं घोषित की गई है। जीवन बीमा की का० पद्मिनी ने कहा कि उन्होंने एक महिला समिति बनाई है; उनके पास पालना या अवकाश-गृह की कोई सुविधा नहीं है।

महा अधिवक्ता के कार्यालय की एक पदाधिकारी और गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रतिनिधि का० उर्सूला फ्रेंसिस ने कहा कि समन्वय समिति के नियंत्रण पर 10 प्रतिनिधि आए हैं। उनके अपने महिला अधिवेशन में 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि प्रोन्नति आदि मामलों में लैंगिक आधारों पर भेदभाव होता है। महिलाओं के प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने कमेटी से निवेदन किया कि छुट्टियों में और प्रशिक्षण की मांग की जाए।

रबर टैपिंग वर्कस का. फातिमा बीबी ने कहा कि उन्हें दैनिक मजदूरी के रूप में मात्र तेरह रुपये मिलते हैं।

आई एस आर ओ की एकमात्र प्रतिनिधि का० सुब्बा, लक्ष्मी ने कहा कि यद्यपि 1000 से ज्यादा महिलाएं इस केन्द्रीय संस्थान में काम कर रही हैं, वे संगठन में काम करने को हिचकती हैं। उन्हें पालना की सुविधा नहीं। उन्होंने उन महिलाओं को संगठित करने में समन्वय समिति की मदद मांगी।

इंजीनियर और इलेक्ट्रीसिटी ऑफिसर्स से एसोसिएशन की प्रतिनिधि का० शांता ने भी कहा कि हलांकि कामकाजी महिलाएं संगठन में सक्रिय हैं पर अफसर पर्याप्त रुचि नहीं लेतीं।

शिल्पी, निर्माण को-ऑपरेटिव, म्यूनिसिपल व कारपोरेशन, विश्वविद्यालय, सरकारी एवं निजी शिक्षक,

ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की कानपुर बैठक के फैसले

ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू. की बैठक 19 और 21 जुलाई 90 को हुई। कमेटी की दो बैठकें हुईं जिनमें कामकाजी महिलाओं की कई समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ—जैसे—उच्चतर कमेटियों में उनकी शिरकत और प्रोन्नति एवम् का० विमल रणदिवे, सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। राज्यों के निम्नांकित सदस्याएं वहां मौजूद थीं—

1. का० संध्या शैली और 2. का० संध्या त्रिपाठी (म. प्र.) 3. का० लीला दास 4. शिबानी दास गुप्ता 5. मिनाती चक्रवर्ती 6. लक्ष्मी दास गुप्ता 7. गार्गी मुखर्जी 8. का० आरती दास गुप्ता (प. बंगाल) 9. का० एम. ईश्वरी 10. कृष्णाताई 11. उमा माहेश्वरी 12. परमेश्वरी 13. का० टी. प्रेमा (तमिलनाडु) 14. का० एस. पुण्यवती (आंध्र) 15. का० एम. एम. राजम्मा (कर्नाटक) 16. का० लक्ष्मी सहगल (उत्तर प्रदेश) 17. का० विमल रणदिवे (केन्द्र) दूसरी बैठक में 18. का० सुशीला गोपालन 19. एम. के. कमलाम्मा (केरल) 20. निशा रॉय 21. दीपाली बोस (प. बंगाल) और 22. पी. गंगाम्मा (प. बंगाल)।

का० लक्ष्मी सहगल ने दोनों बैठकों की अध्यक्षता की। कामकाजी महिलाओं के आंदोलन की पहल करने वाले का० बी. टी. आर. को श्रद्धांजलि दी गई। का० सरोज मुखर्जी को भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथियों के परिचय के बाद का० विमल रणदिवे ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट की मुख्य बिंदुएं थीं धनबाद सभा के बाद कामकाजी महिलाओं के आंदोलन के विकास और संघर्ष की दिशा और एक्जेक्यूटिव इकाईयों में महिलाओं की प्रोन्नति, समन्वय समितियों का गठन ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. के लिए नई सदस्याओं का 'चयन, डब्ल्यू. एफ. टी. यू. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, टी. यू. आई. आदि अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर हमारे कार्य के प्रभाव।

2. विमान परिचारिकाएं तथा नर्सों जैसे नए तबकों ने हाल में हमारे नेतृत्व से खुद को जोड़कर समन्वय समितियां बनाई हैं। रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जहां मध्यवर्गीय महिलाओं एवं नए तबकों में हमारा कार्य परिवर्द्धित हो रहा है। सीटू के अन्दर महिलाओं की गोलबंदी का कार्य अभी भी नजरअंदाज हो रहा है। वर्गगत तौर पर वे संगठित नहीं हैं। सीटू उतना ध्यान इधर नहीं दे रही जितना उसे देना चाहिए।

3. रिपोर्ट में वर्णित एक और बिन्दु की सीटू एवं अन्य ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व के अन्दर प्रभावी सामंती प्रवृत्तियां और इस संदर्भ में नारियों ने उनकी समस्याएं न उठाने के लिए नेताओं की आलोचना की। इस आलोचना का स्वागत होना चाहिए और आशा की जाती है कि नेतृत्व अपने को सुधारेगा।

4. सचिव ने यह भी कहा कि फेडरेशन और एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित पत्र महिलाओं की समस्याओं उनके आयोजनों को जगह देते हैं।

5. आंगनवाड़ी महिलाओं को सबसे ज्यादा शोषित तबके को संगठित किया जा रहा है और 7 अगस्त को एक प्रदर्शन होगा जिसमें भारी तादाद में राज्यों से महिलाएं दिल्ली आएंगी।

6. बंबई और केरल में हमारे प्रयासों से आयोजित रेलकर्मी महिलाओं के अधिवेशनों की विशेष चर्चा हुई। ग्वालियर में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के तत्वावधान में एक विचार-गोष्ठी हुई जिसमें 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट ने तमिलनाडु में हर स्तर पर चल रहे व्यवस्थित कार्य का भी उल्लेख किया—जहां यूनियन नेतृत्व और उद्योगों की कामकाजी महिलाएं साथ जुटकर सामान्य मांगों पर एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पुरुष नेतृत्व इस बात का विशेष खयाल रखता है कि महिला समस्याएं उपेक्षित न हों।

7. रिपोर्ट ने महिलाओं की सदस्यता बढ़ाने के प्रति ढिलाई की आलोचना की। फैक्टरियों व ऑफिसों में इस कार्य को गंभीरतापूर्वक किया जाना है। तमिलनाडु के कई यूनियनों ने महिलाओं को समितियों में, पदाधिकारी पदों पर भी लिया है।

8. का० विमल रणदिवे ने बंगाल समन्वय समिति की अकार्यशीलता पर खेद प्रकट करते हुए साथियों से अपनी समस्याएं रखने को कहा चूंकि मुद्दा बार-बार बहस के लिए उठ रहा है। जबकि कामकाजी महिलाओं के

अनेक संघर्ष हो रहे हैं, प० बंगाल की समन्वय समिति की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही। हलांकि त्रिपुरा के साथी समिति बनाने की बात पर राजी थे, और कामकाजी महिलाएं काफी तादाद में आती हैं, त्रिपुरा में अभी तक समन्वय समिति बनाना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार, उ. प्र., दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि के पास उचित कमेटी भी नहीं है, न ही उनकी कार्यशीलता अच्छी है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी में राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा की महिलाएं आ रही हैं। दिल्ली और दुर्गापुर में नर्सों को संगठित किया जा रहा है। पंजाब की वर्तमान स्थिति और वहां के कार्य में वृद्धि का भी रिपोर्ट में विशेष उल्लेख हुआ।

9. उन्होंने बताया कि ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. और एड्वा के तहत कार्य एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं यदि हम दोनों संगठनों को मजबूत करें और दोनों के कार्यों में समन्वय स्थापित करें।

10. व्वायस ऑफ वर्किंग वीमेन और कामकाजी महिला के मूल्य 2 रु. तक बढ़ाये जाने पर उन्होंने कहा कि सीटू पत्र अभी काफी प्रसार में हैं। सभा में उपस्थित हर सदस्य ने मूल्य बढ़ाकर 2 रुपये करने की उनकी सलाह की अनुशंसा की।

11. अंत में उन्होंने निम्नांकित कार्यक्रम विचारार्थ प्रस्तुत किया—

(क) आंगनवाड़ी सम्मेलन सितंबर-अक्टूबर, 1990 में हो। जगह एवं तिथि तय होनी है।

(ख) सीटू सम्मेलन के साथ फरवरी 1991 में कामकाजी महिलाओं का दो दिवसीय सम्मेलन।

(ग) जहां कहीं भी उनका गठन न हुआ हो वहां समन्वय समितियां बनाई जाएं और नेताओं को पदाधिकारी बनाया जाए।

(घ) कामकाजी महिलाओं से संबद्ध कानूनों को लागू करने, ज्यादा रोजगार के लिए संघर्षों का आयोजन।

(च) अखिल भारतीय स्तर पर नर्सों का संगठन।

रिपोर्ट पर बहस

का० संध्या शैली ने भोपाल की गैस त्रासदी की शिकार महिलाओं के सीटू के अन्दर संगठन पर रिपोर्ट पढ़ी। कई जगहों पर आंगनवाड़ी महिलाएं हमारे नेतृत्व के तहत लामबंद हो रही हैं। ग्वालियर की गंजी फैक्टरी की कामकाजी महिलाएं सीटू के तहत हैं। शहडोल की संध्या त्रिपाठी ने रिपोर्ट के समर्थन में और तथ्य प्रस्तुत किये। सी. एम. डब्ल्यू. ओ (कोयला) के पास अपनी मातहत नर्सों के लिए एक नीति होनी चाहिए। कोयला क्षेत्र की नर्सों ने यहां खुद को अपने 10-सूत्री मांगपत्र पर जनवरी 1990 में संगठित किया। तब जाकर उन्हें पोशाक भत्ते मिले।

का० उमा माहेश्वरी : (तमिलनाडु समन्वय समिति की सचिव) ने रिपोर्ट में एक संशोधन सुझाया। जीवन बीमा निगम के साथ-साथ साधारण बीमा निगम भी ट्रेड यूनियनों में महिलाओं को गोलबंद करने की कोशिश कर रहा है। अतः जी. आई. सी. को भी एल. आई. सी. के साथ उल्लेख मिलना चाहिए था। (इसे मान लिया गया) नारकोइल और मद्रास में उनके दो सम्मेलन हुए थे और समितियां बनाई गई थीं। आंगनवाड़ी में पांच संगठन हैं और अधिकांशतः हमारे समर्थक है। 10 जुलाई को उन्होंने मद्रास में कल्याण विभाग के समक्ष प्रदर्शन का आयोजन किया था। तमिलनाडु में एक 25 सदस्यीय नई कमेटी बनाई गई है। इसमें एल आई सी, जी आई सी, विद्युत, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आये थे। तमिलनाडु में आई. सी. डी. एस. कर्मचारी राज्य सरकार की मदद से 10/- और 15/- दैनिक वेतन पर 3-4 महीने से ठेके पर लगाए गए हैं।

कर्नाटक की **का० राजम्मा** ने बैठक को 10 अप्रैल को हुई प्लांटेशन, बीड़ी, कपड़ा आदि की महिलाओं के सम्मेलन के बारे में रिपोर्ट दिया। अभियान में दूरी और निरक्षरता की समस्याएं आड़े आती हैं। नहीं तो महिलाओं को हम ट्रेड यूनियन कार्यों के लिए तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एल आई सी और बैंक की महिलाएं एड्वा से जुड़ती हैं। कपड़ा फैक्टरी में तमाम पदाधिकारी महिलाएं हैं, पर सीटू नेतृत्व महिलाओं को नहीं चाहता क्योंकि वह मानता है कि वो प्रबंधन के प्रति नरम होती हैं। दूसरी ओर प्रबंधन वही नेतृत्व चाहता है। नतीजा यह हुआ कि सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक में बीड़ी उद्योग संकट में है। दो दिनों के काम के बाद भुखमरी की स्थिति होती है। । तेंदु-पत्तों की काला-बाजारी के चलते महिलाओं को 8 या 9 रु० प्रति हजार

बीड़ी के दर पर काम करना पड़ता है। हलांकि महिलाएं काम करती हैं, इसे पूर्तिकारक वेतन माना जाता है।

प्लांटेशन में मशीनीकरण की वजह से कॉफी मजदूरों को बेकाम किया जा रहा है। एक मशीन 20 औरतों का काम करता है।

हैंडलूम मजदूर, मंडल पंचायत मजदूर 65/- प्रति महीना पाते हैं। उन्हें पूर्णकालिक मजदूर माना जाता है। शिक्षित महिलाएं टंकक (टाइपिस्ट), क्लर्क आदि हैं। ये कर्मचारी 15 अगस्त को अपना अधिवेशन करेंगे। ये राज्य सीटू कमेटियों में महिलाएं हैं पर वे पदों पर नहीं हैं। बीड़ी फेडरेशन में 3 पदाधिकारी महिलाएं हैं। प्लांटेशन में एक सहायक सचिव और 3 एक्जेक्यूटिव कमेटी सदस्याएं हैं। पत्र की कीमत बढ़ाकर 2 रु० कर देने पर वह सहमत थीं।

आंध्र की का० पुण्यवती ने कहा कि उनकी काडरों की समस्या है। उनकी समन्वय समिति बेकार है। हमने आंगनवाड़ी 20 में से 8 जिलों में शुरू किया। आंगनवाड़ी की समस्याएं उठाने के बाद महिलाएं हमसे जुड़ीं और हम उनकी समस्याओं का हल कर सकती थीं। हैदराबाद में सरकारी क्षेत्र में हमारा काम है पर कामकाजी महिलाओं से कोई सपर्क नहीं। आई. डी. पी. एल. में कामकाजी महिलाएं ट्रेडयूनियन की नेता हैं। समन्वय समिति के गठन के बाद हमारे ट्रेड यूनियन नेता कामकाजी महिलाओं की समस्याएं उठा रहे हैं। उनकी सलाह थी कि कुछ एड्वा कार्यकर्त्ताओं को सीटू के ट्रेडयूनियन क्लासों में ट्रेडयूनियन कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाए। दिसंबर में सीटू सम्मेलन के साथ-साथ कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन भी होगा।

तमिलनाडु की का० **ईश्वरी** ने सवाल किया कि राज्य समन्वय समिति के दूसरे सदस्य क्यों उपस्थित नहीं हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के कार्यों की चर्चा रिपोर्ट में नहीं है। हमें अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य मांगें रखनी चाहिए और असंगठित मजदूरों का आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। पंजाब में 6 महीने की छुट्टी है। इस मांग को अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं लिया जा सकता? विमान परिचारिकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होने का समाचार क्या कामकाजी महिला में प्रकाशित किया गया? (इसे पिछले अंक में छापा गया है) ?

हर राज्य का कार्य पुस्तिका के आकार में प्रकाशित होना चाहिए। मद्रास की तरह हर राज्य को उद्योग-आधारित रिपोर्ट देनी चाहिए। हमारी केन्द्रीय समिति उन राज्यों की मदद करे जहां काम कमजोर है। इस कमेटी को वृहत्तर बनाकर इसमें सभी राज्यों के संचालकों को शुमार किया जाए। अपने भाषण का समापन उन्होंने यह कहते हुए किया कि कामकाजी महिलाओं के बीच कठिन श्रम करके ही हम का० सी. टी. आर. को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

का० गार्गी मुखर्जी [प० बंगाल] का कहना था कि सीटू की तमाम जिला समितियों में हमारे यहां सीटू के अन्दर उपसमितियां हैं। जहां कहीं भी महिलाएं असंगठित हैं हम उन्हें अपने परचम तले लाने की सफल कोशिश करती हैं और अब हम असंगठित क्षेत्र से जुड़ रही हैं। बंगाल लैंप और पॉटरीज जैसी कई फैक्टरियां बंद हैं। मशीनीकरण अपनाकर वर्तमान फैक्टरियां महिलाओं को छांट रही हैं और मजदूरों की सेवा खत्म करने के बाद नई बहालियां नहीं की जा रही हैं। हलांकि निम्नस्तरीय कमेटियों का कार्य अच्छा है, केन्द्रीय स्तर पर कमेटी ढंग से नहीं चल रही। अब हम पंचायतों के माध्यम से खेत-मजदूरों को संगठित कर रही हैं।

शिवानी सेनगुप्ता (प० बंगाल) ने कहा कि वे प० बंगाल में कामकाजी महिलाओं से संबद्ध रिपोर्ट के मत से सहमत हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम कामकाजी महिलाओं के बीच काम नहीं करते। असंगठित क्षेत्रों में हम उन्हें निर्माण, रेडीमेड कपड़ा आदि उद्योगों में जिलों के आधार पर संगठित कर रहे हैं। 'इन्जेक्शन' फैक्टरियों में कितनी महिलाएं सीटू के परचम तले काम कर रही हैं। बीड़ी उद्योग में महिला मजदूरों को समान मजदूरी नहीं मिलती और हमारे यूनियन इस मसले को उठाना चाह रहे हैं। महिलाओं के मुसलमान होने से थोड़ी दिक्कतें भी हैं। हलांकि प० बंगाल में पुरुष प्रभुत्वशीलता है पर पुरुष साथी इससे मुक्त हो रहे हैं। कामकाजी महिलाएं कार्य-पदों पर भी हैं। यहां अन्य राज्यों की तरह काडरों की समस्या नहीं है। सीटू अभी भी अपना, समान वेतन आदि के लिए लड़ रही है और जहां भी वह ताकतवर है, इन मांगों को मनवा रही है। फिर भी ए. आई. सी. डब्ल्यू. को उनके संघर्ष में अपनी भूमिका अदा करनी है और यह हमारी कमजोरी है कि हम उचित ढंग से कार्य

नहीं कर सकते।

का० लीला दास (प० बंगाल) ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा कि समन्वय-समिति की भूमिका स्पष्ट नहीं है। प० बंगाल के उपसमितियां उचित निर्देशन के अभाव में ढंग से काम नहीं कर सकतीं। हलांकि वहां पालने हैं, माताएं उन्हें अपने रिहायशी इलाकों में चाहती हैं।

उत्तर प्रदेश का का० लक्ष्मी सहगल का मत था कि उनका कामकाजी महिलाओं का एक सम्मेलन काफी पहले हुआ था। हिस्सा लेने वालों को बीड़ी के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं देने की धमकी दी गई थी। एल. आई. सी. की महिलाएं समस्याएं लेकर हमारे पास आती हैं। हमारा आधार बहुत मजबूत नहीं है और न ही कोई अलग कमेटी या समन्वय-समिति ही है। सूती उद्योग की महिलाओं को निकाल फेंका गया था। हम आंगनवाड़ी में भी संगठन बना रहे हैं। परिवार नियोजन के लिए आंगनवाड़ी नारियों को मजबूर किया जा रहा है।

दिल्ली की रिपोर्ट का० विमल रणदिवे ने प्रस्तुत की। सी. सी. डब्ल्यू., दिल्ली ने एड्वा के साथ मिलकर कई मुद्दों, जैसे, मूल्यवृद्धि, सती अभियान, 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आर. बी. आई., एल. आई. सी, की, में महिला आवासों को लेकर, फंड इकट्ठा करने आदि पर कार्य किए गए। समन्वय समिति के हस्तक्षेप के बाद, एल. आई. सी. प्रबंधन ने शौचालय, प्रकाश आदि की सुविधाएं दीं। हमने आंगनवाड़ी महिलाओं की कई बैठकें की पर यूनियन बनाने में असफल रहीं। समाज कल्याण कर्मचारी यूनियन के संघर्ष के चलते उन्हें 200/- पेंशन प्रति महीना मिलने लगा। दिल्ली समन्वय समिति एक्स में नर्सों की यूनियन बना पाई और सेवा मुक्त की गई 11 नर्सों को पुर्नस्थापित करवा सकी। गुरू तेगबहादुर अस्पताल में भी 248 नर्सों में से 126 की सदस्यता के आधार पर यूनियन बनाया गया। दिल्ली समन्वय समिति के पास काडर का सख्त अभाव है और वह एक होल-टाइमर रखने की सलाह देती है।

तमिलनाडु की का० कृपाकाई ने पंजाब के 6 महीने के मातृत्व अवकाश की सूचना को प्रसारित करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा महिला प्रतिनिधिमंडल की रूस-यात्रा रिपोर्ट में जोड़ी जानी चाहिए। उनका मत था कि आंगनवाड़ी प्रदर्शन में अन्य यूनियनों के बधाई-संदेश आने चाहिये। राज्य में एक अलग कार्यालय और कार्यकर्त्ता कामकाजी महिलाओं के कार्य के लिए विशेष तौर पर होने चाहिए।

ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. को दूसरी बैठक

दूसरी बैठक 21.7.90 को हुई। तमिलनाडु की रिपोर्ट के बाद का० कमलाम्मा और का० सुशीला गोपालन की बारी आई। उन्होंने कहा कि केरल के तमाम जिलों में जिला समन्वय समितियां हैं। कामकाजी महिलाओं के कालीकट में 14-15 जुलाई को हुए सम्मेलन में 310 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधि विभिन्न उद्योगों, फेडरेशनों, राज्य एवं केन्द्र सरकार क्षेत्रों से आये थे। का० भानुमति को अध्यक्षा और का० नजीमुन्निसा को सचिव चुना गया।

एक 51 सदस्यीय समिति चुनी गई। सीटू नेता भी मौजूद थे। हमारे यहां समन्वय-समिति और एड्वा के बीच सहयोग है और हमारी राय में दोनों एक दूसरे की पूरक हैं।

प० बंगाल का का० आरती गुप्ता ने अपने राज्य की कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा इस आशय के निर्देश केन्द्र से दिए जाने चाहिएं कि क्या किया जाए, कार्य उद्देश्य क्या है आदि। हलांकि कई सीटू में पदाधिकारी महिलाएं हैं, हमें रेलकर्मी महिलाओं और एल. आई. सी. से जुड़ने में परेशानी महसूस होती है। उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि केरल में डाक व तार जैसे फैडरेशन और यूनियनें कैसे एक मंच पर काम कर पाते हैं।

इस तरह सचिवीय रिपोर्ट पर बहस समाप्त हुई। बातचीत काफी फलप्रद रही और इससे समितियों की कार्यशैली, कार्यों और दिक्कतों का पता चला। महसूस किया गया कि अन्य राज्यों में भी समन्वय समितियां बनाई जाएं और कमजोरियों पर विजय पाई जाए।

भविष्य के कार्यक्रम

1. अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू.) ने तय किया कि फरवरी में सीटू सम्मेलन से पहले अखिल भारतीय

[शेष पृष्ठ 15 पर]

तमिलनाडु कामकाजी महिला समन्वय समिति की रिपोर्ट

आगे संधनबाद सभा के बाद तमिलनाडु ए आई सी सी, डब्ल्यू डब्ल्यू की गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है—

कामकाजी महिलाओं का अधिवेशन : डब्ल्यू डब्ल्यू सी सी का ऐतिहासिक अधिवेशन, जिसमें का० बी टी आर अन्तिम बार उपस्थित हुए, 20 सितंबर 1989 को नागरकोइल में हुआ । पूरे तमिलनाडु से 200 प्रतिनिधि अधिवेशन में आए और 35 साथियों ने बहस में भाग लिया । भविष्य के कार्यक्रम हेतु हुए इस अधिवेशन में कामकाजी महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी 12 सूत्री मांगें तैयार की गईं ।

तमिलनाडु राज्य समन्वय समिति की बैठकें : समन्वय समिति की बैठक 12 मार्च, 1989 को त्रिची में हुई, जिसमें 9 जिलों से 15 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बहस की । का० कृष्ण बाई धनबाद बैठक के फैसले पर रिपोर्ट पेश की ।

समन्वय समिति की अगली बैठक त्रिची में 25.6.89 को हुई । 7 जिलों से 10 प्रतिनिधियों ने मिलकर 11 सूत्री ज्ञापन तैयार किया 10 जुलाई को आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों के समर्थन में एक रैली और एक प्रदर्शन, समाज कल्याण विभाग के समक्ष आयोजित किये गए।

राज्य स्तरीय बैठक 4.3.90 को त्रिची में हुई । इस बैठक में कुछ कार्यक्रम तैयारी हुए जिन्हें कामकाजी महिला मंच पूरे तमिलनाडु में कार्यरूप देगा ।

नागरकोइल अधिवेशन के बाद मद्रास जिले ने एक हद तक अपना कार्य व्यवस्थित कर लिया । जिला कमेटी 285.90 और 20 के बीच 5 बार मिली । इन बैठकों का उपयोग भविष्य के कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए और भूत के आम एवं विशेष कार्यों की समीक्षा के लिए किया गया ।

मद्रास जिला समन्वय समिति की कार्य रिपोर्ट : राज्य अधिवेशन के अंत में कामकाजी महिलाओं की मांगों जैसे, पालना, अवकाशग्रह, महिला शौचालय, यातायात सुविधा, कामकाजी महिला आवास आदि पर 12-सूत्री मांग-चार्टर अंगीकृत किया गया । समिति ने 6 से 11 नवंबर के बीच औद्योगिक क्षेत्र में एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया, कामकाजी महिलाओं के बीच पर्चे बांटे गए और मद्रास शहर से 5,300 हस्ताक्षर इकट्ठा मुख्य मंत्री, तमिलनाडु को भेजे गए । एकाध को छोड़कर सभी जिलों ने अभियान में हिस्सा लिया । तकरीबन 12000 हस्ताक्षर पूरे तमिलनाडु से जमा करके मुख्य मंत्री को भेजे गए ।

कामकाजी महिलाओं की परिवहन समस्याओं को लेकर एक पत्र भी तमिलनाडु मुख्यमंत्री को दिया गया । राज्य स्तरीय कमेटी की त्रिची सभा (4.3.90) को निम्नांकित निर्णय लिए गए :

हस्ताक्षर अभियान 31.3.90 के अंत तक चलाया जाना चाहिये और हस्ताक्षर राज्य-सरकार को भेजे जाने चाहिए ।

सभी जिले 25-4.90 को कामकाजी महिलाओं की मांगों पर 'मांग दिवस' मनायें । औद्योगिक कामकाजी महिला केन्द्रों आकर्षण के केन्द्र होने चाहिएं और मांगों के पर्चे जिलाधीशों या संबद्ध अधिकारों को दिए जाने चाहिए ।

कामकाजी महिलाओं को बेकारी के खिलाफ चल रही अभियान समिति के साथ आवाज उठाकर इसे सफल बनाना चाहिये ।

पालना की उपलब्धता पर, हर 200 कामकाजी महिलाओं के लिये एक, के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य ।

कामकाजी महिलाओं के विकास कॉरपोरेशन के लिये हर जिलों 8-3-90 को मुख्य मंत्री को तार भेजे ताकि स्थायी रोजगार-सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

मांग दिवस : मद्रास शहर के औद्योगिक इलाकों को मुख्यत: केन्द्र बनाकर मांग दिवस मनाया गया, आम महिलाओं द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं पर बातें हुईं, साझे कार्रवाइयों में एकता और समर्थन पर बल दिया गया । हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि यह आमतौर पर और विशेषकर अम्बाटूर औद्योगिक इलाके में पूर्णरूपेण सफल रहा । सीटू की मदद से एक नुक्कड़ बैठक का आयोजन भी किया गया । बैठक के अंत में कुछ महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर हमसे संपर्क किया । इसमें

एड्वा ने भी हमारा सहयोग किया। उपरोक्त ज्ञापन मुख्य मंत्री और श्रमसचिव को भेजे गए।

बेकारी के खिलाफ अभियान समिति : मद्रास जिला समन्वय समिति की बैठक में सी सी ए यू में हमारे कार्य पर बातचीत हुई और आयकर नई योजना तय की गई। हम मुख्य तौर पर अम्बाटूर, एम ई पी ग्रेड, तिरूवन्मियूर आदि इलाकों में केन्द्रित रहे और खासतौर पर मद्रास मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, जहां तकरीबन 10,000 महिलाएं शोशाक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में लगी हैं। स्थान पर सुरक्षा का जबर्दस्त पहरा था और किसी बाहरी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। योजनानुसार, कामकाजी महिलाएं, स्थानीय कमेटी की मदद से एड्वा और अहने प्रवेश के इर्दगिर्द एक चक्कर बनाया और करीब 6000 पर्चे बांटे। इससे वे सी सी ए यू की मांगों को सुनने लगीं। परिणाम हुआ कि कई महिलाएं रैली में आने की इच्छा प्रकट करने लगी। और अपनी मुश्किलें हससे बांटने को प्रस्तुत हो गई, हमारे संगठन के बारे में पूछताछ करने लगीं।

इसी बीच मद्रास समन्वय समिति ने कई संघर्षों में भी हिस्सा लिया। रीड रिलेज इक्लेक्ट्रॉनिक्स, तिरूवन्मियूर: इस इलेक्ट्रॉनिक कं० मजदूर ने पिछले 65 दिनों से हड़ताल पर है। मजदूर अपने विकल्प की यूनियन (सीटू) के साथ होना चाहते थे। जबकि प्रबंधन उन्हें इंटक में रहने देना चाहता था। 6 मजदूर (यूनियन कार्यकर्ता) निबंबित किये गए। 120 में से जिसमें से 60 महिलाएं थीं, कुछ ही मजदूर प्रबंधन के पिछलग्गू थे। यह हाल के वर्षों में भयंकरतम जुझारू संघर्षों में से एक था। कुंठित प्रबंधन ने गुंडे लाकर 3 मजदूरों को बुरी तरह पिटवाया। प्रबंधन हर मांग मान लेगा यदि वे सीटू से निकलकर वापस इंटक में आ जाएं। महिला मजदूरों के जुझारूपन, निकास हमारा परचम उन्नत है, से हमारा दिल गर्मजोशी से भर उठता है।

महिलाओं के लिए कॉरपोरेशन का विकास

तमिलनाडु राज्य के अधीनस्थ डी. सी. डब्ल्यू. इसी उद्देश्य से बनाई गई है। अनाथ व भुफलिस महिलाओं को प्रश्न दिया जाता है। प्रारंभिक चरणों में कहा जाता था कि उन्हें खुद पर निर्भर रहकर आत्मनिर्भर आर्थिक जिन्दगी जीना चाहिए, और उचित वक्त के साथ उन्हें सरकार समाहित कर लेगी। उन्हें प्रशिक्षण-काल के लिए 225 रु० 'सहायता' राशि दी जाती थी। काफी दु:खद तथ्य था कि छः साल के बाद भी उनका वेतन बढ़ाकर मात्र 275/- किया गया। प्रिंटिंग मशीनों में, इलेक्ट्रानिक संयंत्रों में, आंगनवाड़ी बच्चों के लिए खिलाया उत्पादन में, 305 महिलाये लगी हुई हैं। और एक केन्द्र में उन्हें शौचालय की सुविधा भी नहीं दी गई है। न ही कोई अन्य लाभ। हाल में वे हमारे यूनियन में आई और राज्य सरकार से जंग लड़ने लगी। श्रमनिरीक्षक ने भी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी न देने पर 1,20,000/- का दंड जारी किया। हमारी तरफ से हमने विभिन्न संगठनों से खगभग 12,000/- इकट्ठा किये, हस्ताक्षर अभियान चलाए, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को उनकी स्थायी कार्य-सुरक्षा को लेकर कई तार भेजे। कई अन्य संगठित क्षेत्र के यूनियनों ने भी हमारी पहल पर तार भेजे, कई मंचों पर महिलाओं के शोषण की बात बताई गई ताकि सहानुभूति, समर्थन मिले और लोगों की आम लामबंदी एवं सक्रिय हिस्सेदारी हो सके।

हड़ताल 11.12.89 को शुरू हुई हाल में सरकार ने उन्हें सरकारी सेवाओं में एक साल के अंदर समाहित करने का मौखिक वादा किया, यदि महिलाएं बिना शर्त के काम पर वापस आ जाएं। 20.6.90 को प्रेस खोला गया और प्रबंधन उनके न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रखा है। अन्य दो इकाइयां 5.7.90 को खुली जहां कोई न्यूनतम वेतन नहीं था।

मेरिस अपैरेल्स :—यह एक पोशाक उद्योग है, जहां 450 महिलाएं लगभग 200/- के मासिक वेतन पर काम कर रही थीं। दीवाली के पहले, बिना किसी यूनियन-समर्थन के वे बोनस के लिए दो दिन की हड़ताल पर गई। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद प्रबंधन एक महीने की मजदूरी बतौर बोनस देने को मान गया। लेकिन आगे होने वाले परिणामों को महसूसते हुए, मजदूरों ने सी आई एस यू के निदेशन में प्रबंधन की चुनौती स्वीकारते हुए एक यूनियन बनाई। प्राय: की तरह प्रबंधन कष्ट देने लगा और 12.7.90 को तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। परन्तु, 14.7.90 को तालाबंदी समाप्त हुई और प्रबंधन ने कुछ मांगें स्वीकार कर ली।

ए. एन. सी. प्रतिनिधि का स्वागत : इसी तरह, मद्रास जिला कामकाजी महिला समन्वय समिति ने ए. नन.

सी. प्रतिनिधियों के स्वागतार्थ एक बैठक आयोजित की जिसमें 35 महिलाओं ने भाग लिया ।

ट्रेड यूनियन गतिविधियों में महिलाओं की शिरकत जीवन बीमा निगम : ए. आई. आई. ई. ए. द्वारा जयपुर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार महिला कर्मचारियों को संगठित करने के सचेत प्रयास किए जा रहे हैं। एल. आई. सी. के कायम्बटूर डिवीजन में 4 कामकाजी महिला अधिवेशन किये ताकि महिला साथी आम ट्रेड यूनियन आंदोलन में सक्रिय हो सकें। उन्होंने विभिन्न संगठनों में कार्यरत महिलाओं को संगठित करके नगर समन्वय समिति बनाने में सफलता प्राप्त की। कोवाई शहर की कामकाजी महिलाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने मदुराई डिवीजन समन्वय समिति की मदद से एक जबर्दस्त धरना दिया, और दो अधिवेशन भी दिए। उपरोक्त डिवीजनों में महिला साथीजिला स्तर के नेतृत्व में भी हैं। कई महिला कर्मचारियों ने सम्मेलन में भाग लिया और प्रतिनिधि सत्र में फैलीं।

एल. आई. सी. की एक खास समस्या है कि वहां के एक नियम के अनुसार महिला उम्मीदवार गर्भावस्था में काम पर नहीं लगाई जा सकती। इससे वहां की कामकाजी महिलाएं बहुत खिन्न हैं। ए. आई. आई. ई. ए. और इसकी इकाइयां एल. आई. सी. में महिलाओं को इस अन्याय को हटाने के लिये संगठित करके संघर्ष की तैयारी कर रही हैं।

साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी)—साधारण बीमा निगम में वहां चार सहायक विभाग हैं और 4 अलग यूनियनें वहां हैं। एल. आई. सी. की तरह ही, जी. आई. सी. में भी महिलाओं को सक्रिय बनाने के लिए 3 राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित किए गये हैं। हर साल बड़ी तादाद में महिलाएं सोत्साह इनमें हिस्सा लेती हैं। पहले अधिवेशन में उन्होंने फलना, परिवहन और अवकाश गृह सुविधाओं को लेकर हस्ताक्षर जुटाने का फैसला लिया था, जो पूर्णरूपेण सफल रहा। चूंकि प्रबंधन ने इस मामले में कोई कार्यवाई नहीं की थी अतः ए आई आई ई ए के निर्देशन में महिला कर्मचारियों ने एच ओ के सामने 8.2.90 को एक विशाल धरना दिया। यूनियन संबद्धताओं के आर-पार तकरीबन 200 महिलाओं से ज्यादा ने इसमें हिस्सा लिया। वर्ग प्रथम के अफसर की शिरकत उल्लेख्य है। हाल में, प्रबंधन ने महिला उप-समिति से एक बातचीत की (यह उपसमिति तृतीय राज्य अधिवेशन वादा किया। प्रबंधन ने पालना का उपयोग करने वाली महिलाओं का आंकड़ा मांगा। उपसमिति काम पर है। हाल के समय में काफी महिलाएं प्रदर्शन, फाटक मीटिंगों में भाग ले रही हैं।

इसके अलावा, ए आई आई ई ए महिलाओं को आम जन आंदोलन में सक्रिय बनाती हैं। नेतृत्व में भी कई महिलाएं हैं। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उत्साहित किया जा रहा है, जैसे थ्रिफ्ट सोसायटी में एक महिला निदेशिका है, 2 महिला साथी खेल क्लब कमेटी में हैं।

तमिलनाडु पोषण कर्मचारी एसोसिएशन :—आई सी डी एस कार्यकर्मियों द्वारा 10-7-90 को आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया—रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किये गए। करीब हजारों कर्मचारी आए। इस संदर्भ में, आगे के आंदोलन अभी तक संगठित नहीं हुये हैं।

डाक व तार यूनियन : टेलीफोन विभाग, मद्रास में एक हाल का विकासक्रम है कि मात्र महिलाएं कई चुनावी पदों के लिये खड़ी हुईं और सबों पर विजयी रहीं। तार विभाग में उन्होंने महिलाओं की एक खास सभा की, जिसे सभी महिलाओं ने पसंद किया।

नर्स संगठन : नर्सों को संगठित करने के धनबाद के फैसलले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मद्रास में नर्सों का एक अलग एसोसिएशन है। यह किसी ट्रेड यूनियन से संबद्ध नहीं है। लेकिन तीन महीने पहले उन्होंने एक जबर्दस्त रिले धरना कई मांगों पर किया। जैसे—काम के घंटे की कमी, केन्द्रीय सरकार की नर्सों के समतुल्य वेतन आदि पर। तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने कर्मियों को हड़ताल के अवसर पर साधुवाद दिया। और उन्होंने उनकी तरफ हमारी सहानुभूति पूर्ण रुख को चाहा। फिर भी, उन्हें हमारी लाइन पर संगठित करने के बाद के प्रयास नहीं हुये।

राज्य सरकारी कर्मचारी :—तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने 13-10-89 को एक राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जिसमें 1,500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें से 14 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया। इस विशेष सत्र से ट्रेड यूनियन आंदोलनों के प्रति उनकी चेतना का स्तर परिलक्षित होता है।

विद्युत बोर्ड :—संक्षेप में, 6 महीने की संक्षिप्त

अवधि में विद्युत बोर्ड ने महिला कर्मचारियों को संगठित करने के बड़े-बड़े प्रयास किये हैं। उन्होंने कई जिलास्तर अधिवेशन दिये हैं और सबसे बढ़कर मदुराई में 10-5-90 को उनका राज्य अधिवेशन हुआ। इन आंदोलनों की वजह से, दूसरे एसोसिएशनों प्रबंधन ने हमारे लोगों को दंडित एवं तबाह करना शुरू किया, उन्हें बदली की धमकियां दी जाने लगीं।

व्वॉयस ऑफ वर्किंग वीमेन :—भविष्य में हम राज्य में इसकी बिक्री बढ़ाने के प्रयास करेंगे।

ट्रेड यूनियन आंदोलनों में शिरकत : अब हमारे राज्य में लगभग सभी ट्रेड यूनियनों की महिला शाखाएं हैं। उदाहरणतः राज्य सरकार कर्मचारी, विद्युत बोर्ड, एजी, एल आई सी, डाक व तार यूनियनों में अलग महिला शाखाएं हैं। धीरे-धीरे निश्चित तौर पर ट्रेड यूनियन चेतना विकसित हो रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग एवं मदद की बदौलत हम अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। हर यूनियन से हमारे पास इनको समन्वित करने के लिये एक या दो प्रतिनिधि हैं। समितियों में लिए गए फैसलों को अनिवार्य तौर पर लागू किया जाता है। मद्रास कमेटी में बैंक, बीमा, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, चमड़ा उद्योग, पोशाक दवा एवं विद्युत उद्योग, आई सी डी एस की महिलाएं हैं। मैं गर्व से कह सकती हूं कि तमिलनाडु समन्वय समिति, सीटू की मदद से तमिलनाडु में जड़ें जमा रही हैं और समन्वय समिति एक ताकत बनकर उभरेगी निकट भविष्य में।

[पृष्ठ 11 का शेष]

कामकाजी महिलाओं को उसी तरह का एक दो दिवसीय सम्मेलन हो, जैसा 1979 में मद्रास में हुआ था। इसलिए सम्मेलन से पहले, मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की एक बैठक होनी चाहिए। यदि संभव हो तो बैठक 7 नवबंर को एड्वा के सम्मेलन के पहले हो ताकि साथियों को बार-बार नहीं आना पड़े। प० बंगाल सीटू और महिला समिति से संपर्क करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

2. आंगनवाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन और कार्यक्रम तय किया गया। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, म० प्र०, उ० प्र० आदि से करीब 6000 महिलाएं आ रही हैं। 6-7-8 को रहने आदि की व्यवस्था की जा रही है। एच. एम. एस, एटक, इन्टक (दारा) तथा अन्य यूनियनों के आंगनवाड़ी नेता अनकी मांगों के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं।

3. आंगनवाड़ी महिलाओं का फेडरेशन बनाने के लिए एक सम्मेलन म. प्र. या हरियाणा में अक्टूबर में दो दिनों के लिए होगा जहां 500 प्रतिनिधि आएंगे। अगले सप्ताह अंतिम फैसला लिया जाएगा। तैयारी समिति प्रदर्शन के बाद 7 नवबंर को मिलकर अन्य चीजें तय करेगी।

4. व्वायस ऑफ वर्किंग वीमेन और कामकाजी महिला का मूल्य बढ़ाकर 2/- करने के फैसले को समिति के सभी उपस्थित सदस्याओं ने स्वीकार किया। इसके उपरांत अध्यक्षा को धन्यवाद देकर सभा समाप्त की गई।

का० धनवन्त कौर अमर रहें

का० श्रीमति धनवंत कौर, जो सी. पी. आई (एम) की सदस्या, जनवादी स्त्री सभा (एड्वा) की पंजाब इकाई की उपाध्यक्ष थीं, और उनके पुत्र की हत्या 25 अगस्त 1990 को खालिस्तान आतंकवादियों ने कर दी। वे सीमा पर के गुरदासपुर जिले में अपने गांव की ओर जा रहे थे। का० धनवन्त कौर, पंजाब के आतंक-दग्ध जिले में खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ और राष्ट्रीय एकता के पक्ष में महिलाओं को गोलबन्द कर रही थीं। उनके पति का० अजित सिंह ठक्कर संधू, जिला सी. पी. आई (एम) के सचिवीय सदस्य हैं। वे पार्टी एवं किसान सभा के अग्रणी नेता भी हैं। पूरा परिवार आतंकवादी आक्रमण झेल रहा है। इन तमाम खतरों के बावजूद वे पार्टी के विकास के लिए कठिन कार्य कर रहे हैं। का० धनवंत कौर 40 वर्ष की थीं और उनका बेटा 17 वर्ष का। उग्रवादियों ने दोनों पर हमले किए—लड़का तो घटनास्थल पर ही शहीद हो गया और का० धनवंत कौर एक नजदीक के अस्पताल में घावों से लड़ती चल बसीं।

महिलाओं पर अत्याचारों की केंद्र सरकार न्यायिक जांच कराये

देश के दूर उत्तर-पूर्वी सिरे पर स्थित नन्हे से पर्वतीय राज्य त्रिपुरा में कानून तथा व्यवस्था की मशीनरी पूरी तरह बैठ चुकी है और राज्य की कांग्रेस (आइ)—टी यू जे एस सरकार द्वारा कायम किए गए आतंक राज का निशाना महिलाओं तथा कमजोर तबकों की महिलाओं को खासतौर पर बनाया जा रहा है। यह निष्कर्ष है विभिन्न महिला संगठनों की छः सदस्यीय कमेटी का जिसने 24 तथा 25 अक्टूबर को त्रिपुरा का दौरा किया और विभिन्न अत्याचारों की शिकार हुईं या अत्याचारों के शिकार हुए परिवारों की 70 महिलाओं से मुलाकात की।

कमेटी में नयी दिल्ली आधारित सेंटर फार वीमेंस स्टडीज की निदेशक वीना मजूमदार, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वीमेन की विद्या मुंशी, महिला दक्षता समिति की मंजू मोहन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सुशीला गोपालन, सांसद मालिनी भट्टाचार्य और दिल्ली-आधारित वकील सुश्री कीर्ति सिंह शामिल थीं।

हर तरह के अत्याचार

अपने दौरे के समय कमेटी के सामने यह बात साफ तौर पर आयी कि त्रिपुरा में महिलाओं पर हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं : बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्या, हमले तथा इज्जत लूटने की कोशिश, घरों पर हमले तथा घरों को जला डालना, डराना-धमकाना, सार्वजनिक स्थलों पर निर्वस्त्र कर देना, जीवन यापन के साधनों से वंचित कर देना, जोर-जबर्दस्ती से किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने से रोक देना और न जाने क्या-क्या? कमेटी ने जिन सत्तर महिलाओं से बातचीत की उनमें आठ अल्पवयस्क लड़कियां भी थीं जिन्हें बलात्कार या सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया था।

इन हमलों में सबसे जघन्य पहलू यह है कि बहुत से मामलों में परिवार के सदस्यों को और यहां तक कि बच्चों तक को बलात्कार होते देखने पर मजबूर किया गया था। यह ऐसी चीज है जिसे सरासर पाशविकता ही कहा जायगा और जो पाशविकीकरण करती हैं। सुमित्रा सिन्हा तथा उनके पति राजेश्वर सिन्हा की हत्या की घटना में हत्या से पहले सुमित्रा सिन्हा को सामूहिक बलात्कार का निशाना बनाया गया था और बर्बर कांड उनकी छः वर्षीय पुत्री शुभ्रा तथा चार वर्षीय पुत्र राना की उपस्थिति में किया गया था। कमेटी के अनुसार, जिन महिलाओं ने "अपनी बहू-बेटियों के साथ बलात्कार का प्रतिरोध करने की कोशिश की थी, उन पर लाठियों से प्रहार किए गए थे या उनका गला घोंटा गया था और उन्हें असहाय होकर यह बर्बर अत्याचार अपनी आंखों से देखने पर मजबूर किया गया था।"

इन हमलों की शिकार हुई ज्यादातर महिलाएं आदिवासियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के बीच से हैं और मजदूर, गरीब किसान छोटे दूकानदार तथा ऐसे ही अन्य साधारण परिवारों से थीं।

दो मामलों को छोड़कर हमले की शिकार हुई सभी महिलाओं ने बातचीत में एक ही जवाब दिया उन पर हमले इसलिए किए गए थे कि वे या उनके परिवारीजन, वामपंथी पार्टियों के समर्थक हैं।

पुलिस की सांठगांठ

कमेटी का कहना है कि "पुलिस, अपराधियों को दंड दिलाने में पूरी तरह से विफल रही है।" ज्यादातर मामलों में अपराधियों को पहचाना जा चुका है लेकिन वे उसके बाद भी आजादी से घूम रहे हैं और एकाध मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया तो "फौरन ही रिहा कर दिया गया।" ऐसा बलात्कार के मामलों में हुआ है जो एक गैरजमानती अपराध है। इसके चलते, इन अत्याचारों की शिकार हुई महिलाओं को अनवरत दाब-धौंस के माहौल में रहना पड़ रहा है। यहां तक कि 1988 तथा 1989 के अपराधों के मामले में भी किसी को सजा नहीं मिल सकी है। इसका नतीजा यह है कि इन अत्याचारों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

कोलियरी अस्पताल की नर्सों ने धनबाद में अधिवेशन आयोजित किया

नर्सों और परा-चिकित्सकीय स्टाफ (कोलियरी में कार्यरत अस्पतालों) का अखिल भारतीय अधिवेशन धनबाद में 19 अगस्त 1990 को हुआ जिसमें कोलियरी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की हालत में सुधार लाने के लिए सभी अस्पताली कर्मचारियों का आह्वान किया गया, ताकि 7 लाख कोलियरी खनकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अविलंब उपचार प्रदान किया जा सके।

कोलियरी अस्पतालों में नर्सों एवं परा-चिकित्सकीय स्टाफ की घोर कमी है। मजदूरों को उचित सेवा मुहैय्या करवाने हेतु अस्पतालों में सीटें बढ़ाये जाने की भी जरूरत है। प्रायः स्टाफ की कमी की वजह से मरीज अस्पताल कर्मचारियों को घोस देते हैं। जरूरी है कि स्थिति बदली जाए और तमाम कोलियरी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में स्टाफ अविलंब बहाल किए जाएं। इस अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर डॉक्टरों की कमी दूर करने के उपाय भी किये जाने चाहिए।

नर्सों एवं परा-चिकित्सकीय स्टाफ के लिए रहने की सुविधा न होने से कइयों को दूर दराज से आने के क्रम में जबर्दस्त मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं चूंकि परिवहन सुविधाएं भी नहीं हैं।

केन्द्र सरकार वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, नर्सिंग भत्ता, जोखिम भत्ता, चार्ज भत्ता आदि कई ऊंचे भत्ते नर्सों व परा चिकित्सकीय कर्मचारियों को दे रही है।

कई अस्पतालों में कर्मचारी लंच टाइम नहीं पाते, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है। कोई आरामकक्ष नहीं है और नर्सों तथा चिकित्सकीय स्टाफ के लिए मरीज कमरों, शौचालय प्रसाधनों की इन्तजाम नहीं है।

इसके अलावे, गैर-सामाजिक तत्व प्रायः नर्सों एवं परा-चिकित्सकीय स्टाफ को तबाह करते हैं। कुछ अस्पतालों में मिलने के समय की कठोर पाबंदी नहीं होती, जिसके चलते नर्सों को मरीज देखने में मुश्किलें पेश आती है। डॉक्टर और पदीय पदाधिकारी प्रायः नर्सों एवं परा-चिकित्सकीय स्टाफ को मरीजों के सामने बेइज्जत करते है, जिससे उनकी नैतिक चेतना पर बुरा असर पड़ता है। अस्पताल कर्मचारियों को विटिमाइजेशन और डंडात्मक कारंवाइयां झेलनी पड़ती हैं।

उपेक्षित सी. आई. एल. स्टाफ का संगठन

कोल इण्डिया लि० की कम्पनियों के अस्पतालों की नर्सों एवं परा-चिकित्सकीय स्टाफ का अखिल भारतीय अधिवेशन 19 अगस्त को धनबाद (बिहार) के कृषि धर्मशाला में आयोजित हुआ। अधिवेशन का आयोजन ऑल इण्डिया कोल वर्कर्स फेडरेशन, (सीटू से संबंद्ध) ने किया था और उदघाटन फेडरेशन के महासचिव सुनील बसु ने किया।

विभिन्न कोलियरी राज्यों से 85 प्रतिनिधि आये थे। कुछ आयाएं भी थीं जो विश्राम गृह एवं अपनी अन्य मांगों पर सम्मेलन में बोली।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष एवं सीटू सचिव एम. के. पंधे ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि पहली बार कोयला अस्पतालों के कर्मचारी एक मंच पर आए। खेद की बात है कि ट्रेड यूनियनों ने अब तक इन कर्मचारियों की समस्याओं को उपेक्षित रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस भूल को सुधारने के लिए सीटू सब कुछ करेगी। अधिवेशन में निम्नांकित समस्याएं रेखांकित की गईं। चतुर्थ वेतन समझौते ने हर 100 कर्मचारियों पर एक बिस्तर का निर्धारण किया था लेकिन सी. आई. एल. ने अब तक इसे लागू नहीं किया है। प्रशिक्षण अवधि में नर्सों को मात्र 250 रु० की सहायता राशि मिलती है जो स्पष्टतः थोड़ी है। नर्सों एवं परा-चिकित्सकीय स्टाफ के लिये कोई संतोषजनक प्रोन्नति नीति नहीं है। आदि-आदि। पंधे ने इन कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल को सी आई. एल. अध्यक्ष के पास भेजने और भविष्य के कार्यक्रम तय करने की सलाह दी।

चंडी प्रसाद (महासचिव, बिहार राज्य सीटू), ए. के. राय सांसद (अध्यक्ष, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन), चिन्मय मुखर्जी (एटक) और रामदेव सिंह

महिलाओं के लिए सामूहिक बार्गेनिंग की प्रोन्नति के लिए ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की हिस्सेदारी पर सम्मेलन

इस सम्मेलन का आयोजन श्रम मंत्रालय एवं महिला एवं शिशु विकास विभाग ने 20.9.90 को शास्त्री भवन में किया था। सम्मेलन में एन एल ओ को श्री बारोट, एटक को श्री सान्याल, बी एम एस को श्री प्रभाकर, एच एम एस को श्रीमति कमला सिन्हा, टी यू सी सी को श्री डी डी शास्त्री और सीटू को विमल रणदिवे प्रतिनिधित्व दे रहीं थीं। इन केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के अलावा, सेवा, शिशु कल्याण, सी डब्ल्यू डी एस और जैसे स्वयं सेवी संगठनों और श्रीमती इन्दिरा जयसिंह ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया।

सभा के अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान ने सभी मत-अभिमत सुने। सचिन सुश्री मीरा सेठ द्वारा शुरूआती टिप्पणी के बाद श्री पासवान संगठित व असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की प्रतिशतता बहुत कम है, अतः कामकाजी महिलाओं की बार्गेनिंग स्थिति भी कमजोर है। निर्माण एवं खेती में हजारों महिला कामकाजियों को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। मातृत्व लाभ एवं समान वेतन जैसे महिलाओं से संबद्ध कानूनों का जहाँ तक सवाल है, उन्हें उचित ढंग से लागू नहीं किया जाता। उन्होंने काम की जगह और घर पर महिलाओं की दोहरी भूमिका स्वीकार की। लेकिन वे जानना चाहते थे कि ट्रेड यूनियनों में महिलाएँ कम क्यों हैं? उन्होंने अपना वक्तव्य इस टिप्पणी के साथ समाप्त किया कि कल्याण एवं श्रम दोनों मंत्रालय ट्रेड यूनियनों की महिलाओं को न्याय दिलाने की अपील को सुन रहे हैं।

एच.एम.एस की श्रीमती कमला सिन्हा ने सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्लांटेशन, बीड़ी, निर्माण आदि उद्योगों में विषम वेतन है। उन्होंने खनन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं पर यांत्रिकीकरण के बढ़ते दुष्प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें हजारों की तादाद में काम से निकाला जा रहा है। उन्होंने पासवान साहब से पूछना चाहा कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही।

श्रीमती इंदिरा जयसिंह प्रबन्धन की हिस्सेदारी में महिलाओं के अंश की मांग उठाई। उन्होंने विभिन्न कानूनों के समुचित कार्यान्वयन के लिए चौकीदार समितियों का प्रस्ताव किया। सी डब्ल्यू डी एस की कुमुद शर्मा विभिन्न उद्योगों में विषम मजदूरी के बारे में बोलीं। श्रीमती मीरा पॉल (सेवा) ने असंगठित क्षेत्र की महिलाओं पर अपने विचार जोरदार अंदाज में रखे। उनकी स्थितियों के संदर्भ में उन्होंने ईला भट्ट की "श्रम शक्ति" का जिक्र किया और बताया कि वे खुद अहमदाबाद के टी. एस. ए. सामंती प्रवृत्तियों की शिकार हैं।

सीटू सचिव का. विमल रणदिवे ने अपने पेपर में महिलाओं की वर्तमान स्थितियों का विस्तृत विश्लेषण किया। बहस के लिए प्रस्तुत सरकार के लम्बे दस्तावेज 1979 और 1987 के सीटू दस्तावेजों का कर्जदार है, जिन्हें उन्होंने कामकाजी महिला सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। इस दस्तावेज में ट्रेड यूनियनों में महिलाओं की अल्प हिस्सेदारी स्पष्ट दीखती है—कुल सदस्यता का मात्र 6 प्रतिशत। विषम मजदूरी, पालना की अपर्याप्तता आदि के अनेक मामलों की चर्चा करते हुए उन्होंने सरकार के कार्यान्वयन तंत्र की गरीब कार्य चालन की ओर इशारा किया। "समान वेतन", "महिलाओं के लिए रोजगार" जैसे कुछ समितियां हैं, पर इनकी सभा पिछले 2-3 वर्षों में। ही हुई है। ए आई सी सी डब्ल्यू के 1979 में गठन के बाद कुछ परिवर्तन आया। सीटू से संबद्ध ट्रेड यूनियनों ने महिलाओं से जुड़े सवालों को उठाना शुरू किया और महिलाओं के विशेष सत्र यूनियन सम्मेलनों के साथ होने लगे। लेकिन अभी तक हम यूनियनों में महिलाओं की सदस्यता नहीं बढ़ा पाए हैं।

समाज और साथ ही, ट्रेड यूनियनों में गहरी बैठी सामंती प्रवृत्तियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों का कामकाजी महिलाओं की रक्षा करना भी है, जबकि कानूनों को अगला जामा पहनाने की मुख्य जिम्मेवारी सरकारी कंधों पर है। इस संदर्भ में, उन्होंने परामर्श दिया कि सरकार द्वारा स्थापित वर्तमान सेल काफी नहीं है। ट्रेड यूनियनों एवं महिला संगठनों को सरकारी तंत्र के साथ लिया जाना चाहिए ताकि कानूनों को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

सरकारी दस्तावेज में इंटक, एच एम एस, सीटू आदि के द्वारा विशेष महिला बुलेटिनों की परंपरा की चर्चा थी। पृष्ठ 19 (पैरा 40) में कहा गया कि "सीटू कामकाजी महिलाओं के लिए एक अलग पत्र निकालती है जिसका नाम है "कामकाजी महिला"...पर सीटू के अपने मुखपत्र "सीटू मजदूर" में यह शक्तिशाली गतिविधि परिलक्षित नहीं होती और इस तरह सच्चाई में "सीटू मजदूर" पुरुष मजदूरों का पत्र है और "कामकाजी महिला" "महिलाओं का..." । अपने दस्तावेज में विमल रणदिवे ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि "सीटू के दो पत्र हैं, एक हिन्दी में और एक अंग्रेजी में—जो मजदूर वर्ग मात्र की समस्याओं को समर्पित है, और कामकाजी महिलाएँ उस वर्ग का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। "वर्किंग क्लास" ("सीटू मजदूर"—हिन्दी में) महिलाओं की समस्याओं और उनके संघर्षों को हमेशा जगह देता है।

सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तकनीक की भूमिका और महिला रोजगार पर इसके प्रभावों पर बल देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि तम्बाकू उद्योग में पत्ती की दौनी करने वाले प्लांट के लगाए जाने से उस क्षेत्र में लगी तमाम औरतों को काम से निकाल दिया गया। उन्होंने ऐसे कदमों के विरुद्ध चेतावनी दी—श्रम-संघनित उद्योग चल सकते हैं, मशीनों की जरूरत नहीं है।

उन्होंने असंगठित क्षेत्र और निर्यात तैयारी क्षेत्र की महिलाओं के लिए विधान बनाने की मांग की, जहां कोई भी कानून नहीं लागू होता। श्री सान्याल ने भी महिला समस्याओं पर चंद शब्द कहे।

श्री बारोट अहमदाबाद के सूती मिलों में लगी लाखों महिला मजदूरिनों के बारे में बोलीं, जिनके हितों की रक्षा का प्रयास एन एल ओ कर रहा है। बी. एम. एस. महिलाओं से अपेक्षा रखता है कि वे "अच्छी डाक्टर अच्छी इन्जीनियर बनें पर साथ ही हम उन्हें विश्व में सबसे अच्छी मांओं के रूप में भी देखने की कोशिश करें..." जिस पर तमाम महिला ट्रेड यूनियनिस्टों ने रोष व्यक्त किया।

बहस के दौरान एक बात स्पष्टतः उभरकर आई कि "उनकी समस्याओं की लड़ाई के लिए महिलाओं का अलग यूनियन" बैठक में भाग लेने वालों को मान्य नहीं है। बल्कि ट्रेड यूनियनों के भीतर ही महिलाओं की अलग इकाई बनाकर संयुक्त संघर्ष के रास्ते से उन्हें मजदूर वर्ग के मुख्य संघर्ष से जोड़ना मुख्य लक्ष्य होगा—सभा में हिस्सा लेने वाले तमाम यूनियनों का यह सर्वसम्मत भाव था।

श्री पासवान ने वक्ताओं द्वारा उठाये गये अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दिया और बैठकें भविष्य में अक्सर बुलाने का वादा किया।

अखिल भारतीय नर्स फेडरेशन का दूसरा सम्मेलन

अखिल भारतीय सरकारी नर्सों के फेडरेशन का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन त्रिवेन्द्रम में 26-28 मई '90 के बीच हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र, रास्थान, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक, और केरल के 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए महासचिव श्रीमती जी. एस. खुराना ने कहा कि वे 5 दिवसीय सप्ताह, पोशाक भत्ते में वृद्धि, धुलाई भत्ते, नर्सिंग भत्ते, विशेष वेतन और क्वालिफिकेशन ये आदि जैसे लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार ने फरवरी 1990 के उनके आंदोलन के बाद नर्सों को इस अनुपातों में प्रोन्नति देने की सहमति दी थी—1 नर्सिंग सिस्टर 3.6 स्टाफ नर्सों के लिए, 1 असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेंट 4.5 नर्सिंग सिस्टर्स के लिए, 1 डिप्युटी नर्सिंग सुपरिन्टेण्डेन्ट 250 बिस्तर के अस्पताल के लिए और 1 नर्सिंग ऑफिसर 500 बिस्तर के अस्पताल के लिए। उन्होंने कहा कि आज भी नर्सों के काम के घंटे तय नहीं हैं। उन्होंने नर्सों और नर्सिंग पेशे पर एक उच्चस्तरीय कमेटी की भी चर्चा की और प्रतिनिधियों से रिपोर्ट पढ़कर अपने मंतव्य देने की गुजारिश की।

सम्मेलन ने एक 31-सूत्री मांगपत्र तय किया। फेडरेशन का अगला राष्ट्रीय एक्जेक्यूटिव 1991 में हैदराबाद में तय किया गया।

अखिल भारतीय सम्मेलन के साथ-साथ, केरल सरकारी नर्स एसोसिएशन का भी 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका समापन त्रिवेन्द्रम में नर्सों की एक प्रभावकारी रैली के साथ हुआ।

विमान परिचारिका लीना ठक्कर की मृत्यु पर ए.सी.ई.यू और ए.आई.एच.ए. का संयुक्त वक्तव्य

सुश्री लीना ठक्कर, विमान परिचारिका, ने 26 जून 1989 को इन्डियन एयरलाइन्स में कार्य शुरू किया था। 24 वर्षीया लीना एक सम्माननीय परिवार से आती थीं और एम एस सी थी। उसने अपने सम्बन्धियों को बताया कि उसे उड़ानों से मोहब्बत थी। वह अपने सहयोगियों में भी काफी लोकप्रिय थी।

सुश्री लीना बम्बई-दिल्ली (उड़ान संख्या-IC 434) पर अपने सहयोगियों के साथ कार्यरत थी। दिल्ली के कनिष्क-होटल में वह रात्रि-विश्राम कर रही थी। 20 अगस्त को करीब दो बजे वह अपने 6 ठे तल से कथित तौर पर कूद पड़ीं और अस्पताल जाते-जाते मौत का शिकार हो गईं। लेकिन कई अनजाने तथ्य हैं और छठे तल से कूदना रहस्य में डूबा हुआ है। यूनियन की जांच-पड़ताल से पता चला कि परिचारिका सामान्य थी और हमेशा खुश थीं। इन्डियन एयरलाइन्स कर्मचारियों की जानकारी में उसका कोई प्रेम-सम्बन्ध भी नहीं था और इसलिए निहित स्वार्थों द्वारा प्रचारित किस्से, कि यह प्रेम असफल प्रेम कहानी के नतीजे में की गई 'आत्महिसा' है, को सीधे रद्द कर देना चाहिये। घटना के दिन उसकी घनिष्ठ सहयोगी अपने सम्बन्धी/मां-बाप से मिलने के लिए निकली हुई थी। इस वक्त में, कोई अपराधी उसके कमरे में घुसा और इसके पर्याप्त सबूत हैं कि एक जबर्दस्त लड़ाई हुई, जो उसके शरीर के घावों से स्पष्ट है। इस अपराध की पीड़ा को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने अपनी जिन्दगी समाप्त करने का अतिवादी निर्णय लिया।

हमें जानकारी मिली है कि इस मामले को दबाने में शक्तिशाली निहित स्वार्थी लगे हुए हैं जो इसे एक दुर्भाग्यशाली हादसा बताकर चल देते रहे हैं। उनका तर्क है कि सैंकड़ों ऐसे मामले रोज हो रहे हैं और इसको इतनी गम्भीरता से लेने का क्या तुक है। काले धब्बों की कहानी तो है ही—इसे सामाजिक कलंक कहिए, परिवारक कलंक कहिए या 'कॉरपोरेशन की छवि' अथवा 'समुदाय की छवि' पर ही तरह-तरह की बातें हो रही हैं। हम भी बतौर यूनियन के किसी की छवि पर कीचड़ उछालने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन इस अपराधी को बिना दंड के नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली पुलिस को यद्यपि अपराधी के बारे में पता है पर वह उसे अब तक गिरफ्तार करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है।

विमान परिचारिका/केबिन कर्मचारी की ओर से ए. सी. ई. यू. का एक शिष्टमंडल कार्यवाही निदेशक कैप्टेन बी. सी. खडहले से मिला। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस विषय पर हमारी गंभीर भावनाओं की मुख्यालय तक अविलम्ब पहुंचा दिया जाएगा। हमने कहा कि इंडियन एयरलाइन्स इस मामले में विभागीय कार्यवाई। जांच करने के लिए एक इंच भी नहीं बढ़ा और पुलिस जांच का बहाना लेकर चैन से बैठा हुआ है। सुश्री लीना ठक्कर ड्यूटी पर थी। ऐसे उदाहरण हैं कि अपराधी कार्रवाई के चालू रहने के दौरान भी कर्मचारियों को काम से निकाला गया है। लेकिन विचित्र है कि इस मामले में इंडियन एयरलाइंस दम साधे हुए हैं। क्षेत्रीय निदेशक से हमने मांग की थी कि इंडियन एयरलाइंस को अविलंब विभागीय कार्यवाई शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक सबूतों के आधार पर मामले को सी. बी. आई. को दे दिया जाना चाहिए। हम सी. बी. आई. जांच और अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं और हों।

अधोहस्ताक्षरी जल्द ही दिल्ली में संबद्ध पदाधिकारियों से मिलने वाले हैं। हम आमतौर पर सांसदों और खासकर महिला सांसदों की मदद चाहते हैं ताकि मामले को उचित स्तरों पर आगे उठाया जा सके। इस दिशा में हमने कुछ प्रगति की है और इसके बारे में जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा।

हमने तय किया है कि 28 अगस्त, मंगलवार को 10 बजे एन. टी. बी. पर ऑपरेशन्स विभाग के सामने आम रैली की जाय ताकि परिचारिका के खिलाफ किए गए अपराध की ओर अधिकारियों का बयान खींचा जा सके। यह सच पूछा जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध है।

हम उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि परिचारिकाएं सेक्स-वस्तुएं नहीं हैं। ए. सी. ई. यू. और ए. आई. एच. ए. में हमने संयुक्त तौर पर परिचारिकाओं के खिलाफ लिंगगत विभेदों को मिटाने की लड़ाइयां लड़ी हैं और वास्तव में हमारा संघर्ष जारी है। हमें महिलाओं की इज्जत-मर्यादा की रक्षा के लिए लड़ना ही है। इसलिए हम कर्मचारियों, पुरुष-महिला दोनों, भूमि स्टाफ और हवाई-स्टाफ से अपील करते हैं कि वे इस प्रदर्शन में हिस्सा लें। एन. ई. सी. से एक मोर्चा 28 अगस्त को दस बजे निकाला जाएगा और एयरपोर्ट के बाहर पेरीमीटर रोड को तय करते हुए, जी. एस. डी. के दरवाजे से होकर मूवमेंट कन्ट्रोल तक पहुंचेंगे। एन. टी. बी., जी. एस. डी., कार्गो/के टरिंग/पी. एस. यू. मूवमेंट आदि में कार्यरत स्टाफ मोर्चे में आते जाएंगे और ऑपरेशन्स के सामने जमा होंगे। हम सभी विमान-परिचारिकाओं/उड़ान परिचालकों से अपील करते हैं कि वे वक्त पर आएं और बड़ी तादाद में आएं।

ह०/-	ह०/-
(रूहीन खम्बाटा और आशा मुलगावकर)	(आर रमानाथन और हेमन्त कुमार
एयर इंडिया होस्टेसज एसोसिएशन	एयर कार्पोरेशन एम्पलाइज यूनियन

आत्मदाह पर वक्तव्य

वृन्दा करात (एड्वा), विमला फारूकी (एन. एफ. आई. डब्ल्यू.) और विमल रणदिवे (ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू.) ने निम्नांकित प्रेस विज्ञप्ति 28 सितंबर 1990 को जारी की।

हम विभिन्न राज्यों में छात्र-छात्राओं द्वारा किये जा रहे आत्मदाह एवं आत्मदाह के प्रयासों, जिसके चलते अनेक बेशकीमती जानें बर्बाद हो रही हैं, पर गहरी चिन्ता का इजहार करती हैं। हमारा मानना है कि ये घटनाएं अपने भविष्य को लेकर युवाओं की गहरी कुण्ठा को परिलक्षित करती हैं।

इस संदर्भ में हम महसूस करती हैं कि यह हर माता-पिता की जिम्मेवारी है कि वे अपनी सन्तानों को धैर्य रखने की सलाह दें। खास तौर पर हम महिलाओं इन छात्र-छात्राओं माताओं एवं बहनों से अपील करना चाहेंगी कि वे उनकी उबलती भावनाओं को नियन्त्रित करने का प्रयास करें।

हम इन युवाओं की अपने भविष्य के प्रति चिन्ता समझती हैं लेकिन ऐसे मसले मात्र बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। इसलिए हम छात्र-छात्राओं से अनुरोध करती हैं कि वे बातचीत की प्रक्रिया शुरू करें, चाहे सरकार का जवाब कितना भी विलंबित क्यों न हो।

का० बी. टी. आर. के लेखनों का प्रकाशन

सचिवालय के निर्णय के तहत, सीटू ट्रेड यूनियन आंदोलन पर का० बी. टी. आर. के लेखन को दो या तीन खंडों में प्रकाशित करेगी। का० बी. टी. आर. के जन्म-दिवस की याद में 19 दिसंबर 1990 तक पहला खंड प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। पहले खंड में 1970 से 1980 तक उनके लेख, अध्यक्षीय भाषण आदि होंगे।

सभी यूनियनों, फेडरेशनों और राज्य कमेटियों से आग्रह किया जाता है कि वे इस अवधि के बी. टी. आर. के लेखों आदि को 20 नवंबर तक भेजें। का० बी. टी. आर. के चित्र भी भेजे जाएं।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 1 रुपया

वार्षिक चन्दा : 6 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

[पृष्ठ 2 का शेष]

को भी असम राइफल्स के जवान यातना देने से बाज नहीं आए। चूंकि यह गण परिषद, सी. पी. आई. (एम) के कृषक पक्ष का गढ़ था, अतः असम राइफल्स को गुंडागर्दी करने की पूरी छूट दे दी गई थी।

हमें त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री, सुधीर रंजन मजुमदार और गृहमंत्री के वे शब्द अभी भी याद हैं जो उन्होंने कनक मुखर्जी और विभा घोष, सांसद के नेतृत्व में उनसे मिलने गए एड्वा के शिष्टमंडल एवं अन्य संगठनों से कहे थे। उजान मैदान की घटना के बारे में जवाब-तलब करने और जांच एवं वित्तीय सहायता की मांग करने वाले इन संगठनों को कहा गया था—"महिलाएं आपसे झूठ बोल रही हैं।" जब शिष्टमंडल ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि जनजातीय महिलाएं ऐसे नाजुक मसलों पर झूठ नहीं बोलतीं, वे चिल्लाए, "हां, त्रिपुरा जनजाति महिलाएं झूठ बोल सकती हैं···।" बार-बार यह अभियोग लगाते हुए कि शिष्टमंडल राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित है, उन्होंने आगे कहा, "क्या वे बलात्कारियों की शिनाख्त कर सकती हैं? मैं भी असम राइफल्स की पोशाक पहनकर जा सकता हूं···" इन टिप्पणियों से मुख्यमंत्री का दुःस्साहस जाहिर होता है। शिष्टमंडल एक मुख्यमंत्री के ऐसे असंगत और नीच रवैये से खिन्न होकर विरोध में बाहर चला आया और प्रेस वक्तव्य जारी किया।

हमारी त्रिपुरा नारी समिति एवं अन्य जीवन के ऐसे खतरों के बीच कार्य कर रही है। पिछले दो वर्षों में तकरीबन 122 महिलाओं के बलात्कार हुए जिनमें से अधिकांश जनजातीय हैं। एक नवयुवक छात्र का० अरुण की हत्या और एक चुनाव एजेंट का सिर घोपकर उसे उसकी मां को दिखाना अत्याचारों की क्रूरता रेखांकित करता है। और हाल में बेलोनिया में सुमित्रा और उसके पति राजेश्वर सिन्हा की रात के सन्नाटे में हत्या क्या शब्दों में बयान की जा सकती है? त्रिपुरा के इंका—टी. यू. जे. एस. गठबंधन द्वारा लगाए गए हत्यारे गिरोह अपनी सरकार के प्रतिरोधों को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं। इस तरह के दमन के अलावा सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें कोई चारा नही दीखता।

वर्तमान राजनीतिक स्थिति

त्रिपुरा की वर्तमान राजनीतिक एवं आर्थिक दशा भयानक है। जन वितरण प्रणाली ढह चुकी है। दुकानों में राशन नहीं है, जनजातियों के लिए कल्याण सेवाएं वापस ले ली गई हैं, गांवों में सी. पी. आई. (एम) का बहिष्कार किए बिना कोई जनजातीय परिवार नहीं रह सकता। पार्टी का बहिष्कार करने के बाद भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आम लोग बाजार जाकर चीजें नहीं खरीद सकते। अपनी जान बचाने के लिए हजारों परिवार जंगल या अन्य जगहों पर भाग गए हैं। जबर्दस्ती पैसे वसूल किए जा रहे हैं। पुलिस हमेशा ही प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज करने से इंकार कर देती है, न्यायतंत्र धमकियों के घेरे में है। त्रिपुरा में आज कोई जनवादी तौर-तरीका नहीं चलता।

इसके अलावा वर्तमान इंका—टी. यू. जे. एस. गठबंधन ए. डी. सी. को तबाह करने के लिए अवैध बंगलादेशी प्रवासियों को प्रवेश दे रहा है। इंका-समूहों के बीच आपसी झगड़े की रिपोर्टें आ रही हैं।

नारी समिति हमारे साधुवाद की पात्र है

हमारी त्रिपुरा नारी समिति जिस तरह से काम कर रही है वह प्रशंसनीय है। उन्हें गांवों में महिलाओं से संपर्क करना होता हैं, सन्देश देने होते हैं और सांगठनिक कार्य करने होते हैं। हाल के आतंक के माहौल के बावजूद सदस्यता घटी नहीं है। नारी समिति ने 15 सितंबर को वर्तमान की समस्याओं पर बातचीत के लिए अगरतला में एक अधिवेशन आयोजित किया था।

सी. पी. आई. [एम] और जनसंगठनों द्वारा त्रिपुरा फंड के अखिल भारतीय अभियान के तहत त्रिपुरा के लोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी सहानुभूति दी गई। पूरे भारत के जनवादी लोग त्रिपुरा के लोगों के लिए न्याय की मांग करते हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अविलंब कार्रवाई करके आतंकवादी साम्राज्य से लोगों की रक्षा करनी चाहिए एवं उनके जनवादी अधिकारों को पुनर्स्थापित करना चाहिए।